

NEWS CLIPPINGS

(HINDI DAILIES)

Relating to

the National Summit

on

National Value Crisis and Redressal

Nation's Thinking and Perception

November 18-19, 2008

India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi



Foundation *for* Restoration *of* National Values

TABLE OF CONTENTS

1. Amar Ujala, New Delhi, 18 November 2008
2. Hindustan, New Delhi, 19 November 2008
3. Navbharat Times, New Delhi, 19 November 2008
4. Duniya, New Delhi, 19 November 2008
5. Dainik Bhaskar, New Delhi, 19 November 2008
6. Aaj Samaj, New Delhi, 19 November 2008
7. Jansatta, New Delhi, 19 November 2008
8. Deshbandhu, New Delhi, 19 November 2008
9. Haribhoomi, New Delhi, 19 November 2008
10. Virat Vaibhav, New Delhi, 19 November 2008
11. Mahamedha, New Delhi, 19 November 2008
12. Sandhya Times, New Delhi, 19 November 2008
13. Veer Arjun, New Delhi, 19 November 2008
14. Hindi Mahanagar, New Delhi 19 November 2008

श्रीधरन पढ़ाएंगे राष्ट्रीय मूल्यों का पाठ



नई दिल्ली। मेट्रो में न डॉ. ई श्रीधरन राष्ट्रीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का पाठ पढ़ाएंगे। पाठशाला में पाठ पढ़ाने से पहले अलग-अलग विधा के पुरोधाओं से उनके विचार लिए जाएंगे। पाठशाला में न केवल मेट्रो रेल के कर्मियों बैठेंगे बल्कि उनके आठ लाख यात्रियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। मंगलवार को राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट और उसकी पुनर्स्थापना को लेकर दो दिवसीय सेमिनार शुरू किया जा रहा है। सेमिनार में संसद, कानून का क्रियाकलाप, न्यायपालिका, मोडिया, लोक प्रशासन, कार्पोरेट सेक्टर, शिक्षा और

स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोग आमंत्रित हैं। फाउंडेशन फॉर रीस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज के अध्यक्ष और डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. ई. श्रीधरन ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय मूल्यों में आ रही गिरावट के कारणों को पहचानना होगा। यही वजह है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय सेमिनार में आमंत्रित किया गया है। सेमिनार में राष्ट्रीय मूल्यों पर चर्चा करने को प्रथम सत्र में सबसे पहले लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केजी वासाकुण्णन और स्वामी भूमनंद तिथी विचार रखेंगे। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, शैलू, दीश्वर, सुरेश प्रभु, जस्टिस एमएन वेंकटचलैया संसद के गिरते विश्वास और राष्ट्रीय मूल्यों पर चर्चा करेंगे। स्वामी भूमनंद तिथी ने बताया कि अलग-अलग स्तर के धर्म और योजनाकारों से मिले सुझाव को राष्ट्रीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करने में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूल्यों की धुरि खराब हो गई है। हमारा देश मूल्यों के मामले में प्रबल रहा है, हमें नए मूल्य स्थापित करने को जरूरत नहीं है बल्कि हर व्यक्ति अपने को राष्ट्रीय समझे। मैं भारतीय हूँ, भारत की उन्नति में बाधा के लिए कोई काम नहीं करूंगा। ऐसा करने से देश की उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो कर्मियों के साथ उनके आठ लाख यात्रियों में राष्ट्रीय मूल्य जागृत करने का काम भी किया जाएगा।

MICROFILM

राष्ट्रीय मूल्यों की गिरावट को कैसे करें पुनर्स्थापित जुड़े हर विधा के पुरोधा

आठ कैटेगिरी से जुड़े यिकर किए गए आमंत्रित

आज से शुरू हो रहा है दो दिवसीय सेमिनार

आठ लाख यात्रियों को भी इससे जोड़ा जाएगा

विभाजनकारी राजनीति संविधान के लिए खतरा : बालाकृष्णन

कार्यालय संवाददाता नई दिल्ली

राष्ट्रीय मूल्य संकट और समाधान विषय पर केंद्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया हैबिटेड सेंटर में मंगलवार को शुरू हो गया। फाउण्डेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज की ओर से आयोजित यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है।

सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों ने अपने विचार विस्तार से रखे। लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि काफी संख्या में लोग राजनेताओं की आलोचना करते हैं लेकिन आलोचना करने वाले प्रोएक्टिव नहीं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने कहा कि लोगों को तोड़ने वाली विभाजनकारी राजनीति संविधान के लिए खतरा है। लोगों को तोड़ने वाले विषयों पर आधारित राजनीति खतरनाक है। बहुआयामी समाज में विचारों की विभिन्नता होना स्वाभाविक है और प्रौढ़ लोकतंत्र में मिल बैठकर उसका समाधान निकालना चाहिए। हाल के दिनों में

न्यायपालिका के कई उच्च पदस्थ लोगों पर आरोप लगे हैं। न्यायपालिका रखवाली करती है और उस पर कौन रखवाली करेगा, यह सोचने का विषय है। उन्होंने कहा कि इस समय राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आ रही है।

वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि भारतीय राजनीति के बदरूप शक्ल को दुरुस्त करने के लिए अधिक संख्या में युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हिन्दुस्तान की प्रमुख संपादक मृणाल पाण्डे ने कहा कि वर्नाकुलर प्रेस को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। आज 90 प्रतिशत लोग इसी के पाठक हैं। वर्नाकुलर प्रेस में आधुनिक तकनीक की शुरुआत हो गई है और इसको और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। 12वीं कक्षा तक अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राएं जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो अंग्रेजी भाषा के अधिकाधिक प्रचलन में वे अपने आपको सहज नहीं पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को दोहरे परिश्रम करने की जरूरत होती है।

उग्रता से खतरा-चीफ जस्टिस :
देश के चीफ जस्टिस के. जी. बालकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बेवजह हिंसा और गड़बड़ियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उग्र राजनीतिक विचारधारा हमारे संविधान की नींव के लिए काफी बड़ा खतरा है।

पेज 14

चीफ जस्टिस ने कहा, खतरनाक है उग्र राजनीति

पीटीआई ॥ नई दिल्ली : देश के चीफ जस्टिस के. जी. बालकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बेवजह हिंसा और गड़बड़ियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उग्र राजनीतिक विचारधारा हमारे संविधान की नींव के लिए काफी बड़ा खतरा है। मौजूदा राजनीति और कानून-व्यवस्था पर एक सख्त स्पीच में उन्होंने कहा कि ग्रुपों में भले ही विचारों को लेकर धुवीकरण हो, लेकिन लोगों का समझाने का जरिया टकराव नहीं होना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना किसी सही वजह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इससे आम जनजीवन प्रभावित होता है जबकि बातचीत से किसी भी समस्या का बेहतर हल निकाला जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि प्रजातंत्र में वैचारिक मतभेदों को बातचीत के जरिए पाटा जाना चाहिए।

जिस तरह के समाज में हम जी रहे हैं, विभिन्न सेक्शनों के बीच संघर्ष हो सकता है। लेकिन अगर हमें एक सहिष्णु राष्ट्र बनाना है तो सभी अंतरों को खत्म करना होगा। धर्म, जाति, लिंग, वर्ग और धर्म के नाम होने वाले मतभेद अक्सर प्रायोजित और संस्थागत हिंसा में बदल जाते हैं।

न्यायपालिका पर सवाल उठना
चिंता की बात : चीफ जस्टिस के. जी. बालकृष्णन ने ऐसे मामलों पर चिंता जताई है जिनकी वजह से न्यायपालिका पर ही सवाल उठने लगे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाल के कुछ महीनों में सर्वोच्च न्यायपालिका पर ही कई आरोप लगे हैं। न्यायपालिका नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने वाली वाँचडॉंग है। अब यह सवाल उठने लगे हैं कि वाँचडॉंग को कौन वाँच करेगा? उन्होंने कहा कि सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार से आम नागरिकों को डेली लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वेतनों में फर्क बड़ी वजह हो सकती है।

प्रतिगामी राजनीति की प्रवृत्ति

घातक : मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने देश में हो रही बेवजह हिंसा से लोगों के जीवन में आ रही परेशानी को गलत ठहराया है। दलों की प्रतिगामी राजनीति की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे संविधान का सही ढंग से पालन नहीं हो सकता। बालाकृष्णन ने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को

» शेष पृष्ठ 11 पर

प्रतिगामी राजनीति...

खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास करने की बात कही। बालाकृष्णन ने कहा कि दलों को सटीक तर्कों के साथ एक दूसरे की विचारधारा का विरोध करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मूल्यों के संकट व उसके हल के संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनके अनुसार दलों के विचारों की भिन्नताओं को तर्कों व गंभीर विचार विमर्श के साथ खत्म करना चाहिए। परिपक्व होते लोकतंत्र में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नताएं आना स्वाभाविक है परंतु इसको खत्म करने के लिए धैर्य व समुचित विचार विमर्श जरूरी है। बालाकृष्णन ने कहा कि न्यायपालिका में होने वाली गड़बड़ी लोगों के लिए और दुखदाई है।

राजनीति के आक्रामक तेवर खतरनाक : बालकृष्णन

भास्कर नेटवर्क/एजेंसी. नई दिल्ली. देश के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने आगाह किया है कि विभाजनकारी मसलों पर आक्रामक राजनीति इस देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

उन्होंने न्यायपालिका में नैतिक मूल्यों में गिरावट पर भी चिंता जताई। राष्ट्रीय मूल्यों पर संकट के संबंध में मंगलवार को यहां आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति से इन सिद्धांतों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, जिनकी संविधान में हिमायत की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें निरर्थक हिंसा करके छोटे-छोटे मसलों पर राष्ट्र का धुवीकरण किया गया।

उन्होंने कहा कि बहुलतावादी समाज में मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हम इन्हें उचित ढंग से सुलझा सकते हैं। न्यायपालिका के संबंध में न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने कहा कि यह समाज का पहरदार है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में न्यायपालिका में उच्च स्तर पर आरोप लगे हैं। इससे इस पहरदार की निगरानी के सवाल उठ खड़े हुए हैं।

आक्रामक राजनीति संविधान के लिए खतरा: बालाकृष्णन

पीटीआई, नई दिल्ली

मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने
आगाह किया है कि विघटनकारी मुद्दों



पर आक्रामक
राजनीति देश
के संविधान के
लिए सबसे बड़ा
खतरा है। उन्होंने
न्यायपालिका में
गिरते मूल्यों पर

भी चिंता जताई। 'नेशनल वेल्यू
क्राइसिस एंड रिड्रसल' पर
आयोजित एक सम्मेलन में
बालाकृष्णन ने कहा कि आक्रामक
राजनीति हमारे संविधान के सिद्धांतों
के लिए खतरा है। हाल के समय में
हिंसा के कई ऐसे उदाहरण सामने
आए हैं जब तुच्छ मुद्दों पर लोगों का
धुवीकरण करने की कोशिश की गई
है। बहुलतावादी समाज में मतभेद
लाजिमी हैं लेकिन लोकतंत्र में इन
मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से
समाधान खोजा जाना चाहिए।

आडवाणी ने कहा- देश सेवा के लिए युवा राजनीति में आएँ

जनसत्ता ब्यूरो

दिल्ली, 18 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा राजनीति में आएँ और देश की सेवा करें। मंगलवार को एक गोष्ठी में आडवाणी ने भारतीय राजनीति की धूमिल पड़ती छवि को बदलने की जरूरत भी बताई। राष्ट्रीय मूल्यों का संकट और इसमें सुधार विषय पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए आडवाणी ने कहा कि ज्यादा युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करके ही बदलाव संभव है।

आडवाणी ने कहा कि वे अपने साथी राजनीतिकों खासकर अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारतीय राजनीतिकों की बदनुमा छवि को मिटा डालें। आडवाणी ने पारदर्शिता इंटरनेशनल की

सालाना रिपोर्ट का भी हवाला दिया। जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान काफी ऊपर दिखाया गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में यह काफी नीचे है।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि आजादी के आंदोल के दौरान राजनीति को अच्छा काम समझा जाता था। लेकिन आजादी के बाद मिशन की भावना धीरे-धीरे खत्म हो गई। उन्होंने अफसोस जताया कि भारत में न तो राजनीति में आज कोई मिशन रह गया है और न इसे कोई प्रेश समझा जाता है। उल्टे इसमें खालिस व्यवसायिकता आ गई है।

बकौल आडवाणी मूल्यों में गिरावट केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। बल्कि ईमानदारी और पैसेवर नजरिए की कमी वकीलों, जजों, डाक्टरों और सुरक्षाकर्मियों तक में भी दिखाई पड़ रही है।

युवा राजनीति में आएं : अडवानी

नई दिल्ली, 18 नवंबर

(देशबन्धु)। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवानी राष्ट्रीय मूल्यों के संकट विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में उन्होंने भारतीय राजनीति की धूमिल पड़ती छवि को निखारने पर जोर देते हुए कहा कि योग्य युवा अधिक-से-अधिक राजनीति में आएं और राष्ट्र की सेवा करें। भारतीय राजनीति से प्रेशेवर रुख की कमी के चलते ही राजनीति में मूल्यों की कमी आती जा रही है। आजादी के आंदोलन के समय राजनीति को अच्छा कैरियर समझा जाता था, लेकिन आजादी के बाद धीरे-धीरे यह भावना खत्म हो गई। अडवानी ने साफ कहा कि मूल्यों में गिरावट सिर्फ राजनीति में ही नहीं आई है बल्कि ईमानदार रुख की कमी वकीलों, न्यायाधीशों, डॉक्टरों और यहां तक सुरक्षाकर्मियों में भी दिखाई देने लगी है।

प्रतिगामी राजनीति खतरनाक

हरिभूमि, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश जेजी बालकृष्णन ने कहा कि विभाजनकालीन मुद्दों पर हो रही प्रतिगामी राजनीति देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे मंगलवार को यहां राजधानी स्थित टैचीटेट सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय मूल्य संकट और सुधार पर आयोजित एक सम्मेलन में बोले रहे थे। उन्होंने मौजूदा राजनीति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने न्याय व्यवस्था में नैतिक मूल्यों के क्षय पर भी चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने राष्ट्रीय मूल्य संकट और सुधार पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति का प्रतिगामी होना हमारे संविधान के लिए और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए खतरा है। हाल

के समय में तुच्छ कारणों के लिए राष्ट्र के धुँवीकरण के लिहाज से निरर्थक हिंसा के अनेक उदाहरण देखे गये। श्री बालकृष्णन ने



राष्ट्रीय मूल्य संकट व सुधार सम्मेलन में बोले मुख्य न्यायाधीश

कहा कि बहुलतावादी समाज में मतभेद होना लाजमी है लेकिन लोकतंत्र की परिपक्वता के साथ ये मतभेद सीखपूर्ण तरीके से सुलझे जाने चाहिए। न्याय व्यवस्था के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि यह संयोजन का एक वाचडाग है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में उच्च स्तरीय न्यायतंत्र के खिलाफ आरोप लगे हैं। इससे सवाल उठा है कि वाचडाग पर कौन मजबूर रखेगा। इसके लिए स्वयं राजनीतिज्ञों को ही विचार करने की जरूरत है। इससे पूर्व इस सम्मेलन में सीकराभा अभ्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने देश की विगड़ती और

» संपृक्त 14 पृष्ठ »

सरकार कर रही है न्यायालय के निर्देशों की अवमानना

■ एजेंसी।

नई दिल्ली। पूर्व महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने दावा किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पुलिस सुधार के संदर्भ में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अमल नहीं कर अदालत की अवमानना कर रही हैं।

बेदी ने 'राष्ट्रीय मूल्यों में संकट और सुधार' विषय पर संगोष्ठी में कहा कि उच्चतम न्यायालय



सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए जरूरी है कि पुलिस में चयन के तरीके में बदलाव हो

ने सितंबर 2006 और जनवरी 2007 में पुलिस सुधार को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे लेकिन केंद्र तथा प्रदेश सरकारों ने उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जो न्यायालय की अवमानना है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की पूर्व महानिदेशक ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस में चयन के तरीके में बदलाव हो कानून व्यवस्था को जांच से अलग रखा जाए और पुलिस अधिकारियों के किसी पद पर बने रहने की निश्चित समय सीमा तय की जाए।

उन्होंने कहा कि कई राज्य उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को तैयार नहीं हैं जो न्यायालय की अवमानना है। बेदी ने कहा कि केंद्र

सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए थे कि एक समिति द्वारा ही पुलिस प्रमुखों का चयन किया जाए लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया गया। केंद्र सरकार भी न्यायालय की अवमानना कर रही है। बेदी पुलिस सुधार दो अंतिम किरण बेदी ने कहा कि पुलिस सुधारों के लिए सोराबजी समिति गठित की गई थी। इसके तहत तीन वर्ष तक विशेषज्ञों ने पुलिस

सुधार के लिए रूपरेखा तय की लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्यों की पुलिस ही यह कह रही है कि उन्हें सुधार की जरूरत नहीं है।

आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के पूर्व महानिदेशक डा. कार्तिकेयन ने इस संदर्भ में गृह मामलों की संसदीय समिति के समक्ष दिए सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति के कारण पुलिस प्रणाली पर असर पड़ा है। हमने पुलिस को राजनीतिक मामलों से अलग रखने का सुझाव समिति को दिया है। उड़ीसा सीआईडी के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस में संरचनात्मक सुधार की काफी जरूरत है।■

Mahamedha, New Delhi, 19.11.08

राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए दो दिवसीय सेमिनार आज से

संवाददाता/नई दिल्ली
हमारे देश के मूल्यों के लगातार हो रहे हनन को रोकने के लिए तथा देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मंगलवार से राष्ट्रीय मूल्योत्थान निर्वहन फाउंडेशन के तत्वावधान में इंडिया इंस्टीट्यूट सेंटर में दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा।

फाउंडेशन में मेट्रो मैन समेत पांच नामी लोग शामिल हैं। इस सेमिनार को पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, लोकसभा में विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लोकसभा स्पीकर सोमनाथ धट्टजी, मुख्य न्यायाधीश के. जी. वालाकृष्णन, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, केंद्रीय सर्वोच्च आयोग प्रत्युष सिन्हा और टाटा ग्रुप के रेजिडेंट डायरेक्टर भारत संबोधित करेंगे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को जीएमआरसी के

मैनेजिंग डायरेक्टर ई. श्रीधरन, स्वामी भूमनंदा तीर्थी, भारत आखिल ने संबोधित किया।

स्वामी भूपानंदा ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हमारे देश में मूल्यों की सुरक्षा खतरनाक होती जा रही है। आज मूल्यों की खोरी होने लगी है।

**पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल
कलाम करेंगे सम्मेलन
को संबोधित**

उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी तकत है, लेकिन हमें आज राष्ट्र के प्रति सोचने की जरूरत है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हम उनको आज भी समझ नहीं पाए हैं।

उन्होंने कहा कि आज मानव की अंतरात्मा से खोचना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? तभी हम

आगे प्रगति कर सकेंगे। हमें बौद्धिक स्तर को बढ़ाना होगा तभी हम लोगों को अच्छा ज़िन्दगी के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने मूल्यों को बचाए रखने के लिए ही इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में देश के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और नेता आएंगे जो विचार-विमर्श करेंगे।

एक अच्छी सोच को लेकर समाज में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत का हर व्यक्ति देश की उन्नति में बाधा न बने। मेट्रो मैन ई. श्रीधरन ने कहा कि वह मेट्रो के माध्यम से समाज और अपने यात्रियों में एक अच्छी आदत को बढावा देना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर मेट्रो में सफर करने वाले यात्री भारतीय संस्कृति और नैतिकता का फल पढ़ गए तो जाहिर है कि धीरे-धीरे पूरे देश में इसकी अलख जग जाएगी।

श्रीधरण का नया मिशन

प्रतिनिधि

अब तक आप उन्हें जिस रूप में देखते आए थे, अब उससे अलग नजर आएं। दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे को सक्सेस स्टोरी बनाने वाले ई श्रीधरण देश को और भी कुछ देना चाहते हैं।

वह चाहते हैं कि बाकी संस्थाओं में भी ऐसा ही यूनीक वर्क कल्चर बने। उनमें भी समय की कीमत हो और मॉरल वैल्यूज को महत्व दिया जाए। यानी सब बढ़ें, देश बढ़े। इस मिशन में उनके साथ हैं, रतन टाटा, पूर्व जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, एन विट्ठल, टीएस कृष्णमूर्ति जैसे लोग। सभी कुछ महीने पहले बने फाउंडेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज के एडवाइजरी बोर्ड में हैं और श्री धरण उसके चेयरमैन हैं।



फाउंडेशन ने कम होते राष्ट्रीय मूल्यों पर विचार के लिए दो दिवसीय सेमिनार का इंडिया हैबिटाट सेंटर में आयोजन किया है। आज शुरू हुए सेमिनार में

देश के हर क्षेत्र के विचारकों को बुलाया गया है। फाउंडेशन की स्वामी भूमानंद तीर्थ का भी सहयोग मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में राष्ट्रीय मूल्य सोवंपरि रहा है, लेकिन इसका स्तर गिर रहा है। लालच और स्वार्थ बढ़ रहा है। हम यह भूल गए हैं कि

व्यक्ति की गुणवत्ता ही देश की गुणवत्ता को निर्धारित करता है।

राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा दे हम देश को मूल्यवान बना सकते हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि आखिर व्यक्ति का नैतिक पतन क्यों हो रहा है।

देश की तकदीर बदलने चले नैनो
से लेकर मेट्रो रेल तक के रचनाकार

वीर अर्जुन संवाददाता सखी शिक्षाविद भी खड़ी
नई दिल्ली। दुनिया को नैनो दिखायी दी। पुनरुत्थान
का चमत्कार देने वाले रतन टाटा आंदोलन की इस नयी पुकार पर
दिल्ली को सपनों की रानी के दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन
रूप में मेट्रो रेल देने वाले श्रीधरन आयोजित किया गया और
और भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार मेट्रो में श्रीधरन ने घोषणा की
करने में मशहूर एन विट्टल जैसे कि इस सम्मेलन की आयोजक
समाज के अग्रणी नागरिकों ने फाउंडेशन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ
एक मंच पर एकलुट होकर दूसरा नेशनल वैल्यूज जल्दी ही सम्मेलन
राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान शुरू करें निष्कर्षों को उच्चतम
करने की आज घोषणा कर दी। न्यायालय तक ले जाया।
सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ पुनर्जागरण के राष्ट्रीय अभियान
बनाने लोकतांत्रिक मूल्यों को में पूर्व राष्ट्रपति एव मिसाइल में
बढ़ावा देने और हर क्षेत्र में डॉ. पी. जे. अब्दुल कलाम प्रधान
सुशासन को देश के एजेंडे में न्यायाधीश के जी. बालाकृष्णन
सर्वोपरि रखने के इस अनूठे देश की प्रथम महिला आईपीएस
आंदोलन के बनर तले पूर्व प्रधान अधिकारी किरण बेदी जाने माने
न्यायाधीश एम. एन. वैकटचलैया मंत्रकार एम. जे. अकबर और
तथा स्वामी भूमानंद तीर्थ जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका
संत और विभा पार्थसारथी साराभाई भी शामिल हुए हैं।

खतरनाक है क्षेत्रवाद की राजनीति : बालाकृष्णन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्रवाद की राजनीति देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बालाकृष्णन ने 'नेशनल वेल्यु क्राइसिस एंड रिडेरसल' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश को बांटने वाले मुद्दों पर उग्र राजनीति करना देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्षेत्रवाद की राजनीति हमारे संविधान और संविधान के



न्यायपालिका पर कड़ी टिप्पणी

आदर्शों दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि देश के ध्रुवीकरण के लिए पिछले कुछ दिनों में इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनका कोई मतलब नहीं था। बालाकृष्णन ने कहा कि भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश में मतभेदों का होना स्वाभाविक है, लेकिन लोकतंत्र जैसे-जैसे मजबूत होता है हमें इन मुद्दों का समाधान भी शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका में भी नैतिक मूल्यों का दिनोंदिन पतन होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल के दिनों में न्यायपालिका पर कई आरोप लगे हैं। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर लोकतंत्र के इस पहरेदार पर कौन नजर रखेगा?